मुख्यमंत्री निवास पर ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति, परम पूज्य तुलछाराम महाराज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भेंट कर उनका स्नेहाशीष प्राप्त किया।

ईरान ने की जवाबी कार्यवाही, तेल अवीव के कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया

इज़रायल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी, मिसाइलें दागना बंद नहीं किया तो ''तेहरान जलेगा''

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। यरुशलम द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए अनायास और अनुचित मिसाइल हमलों से भड़के ईरान ने शुक्रवार रात को तेहरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल अड्डों पर इज़राइली हमलों के जवाब में इज़राइल पर भारी मिसाइल हमला किया, जिससे तेल अवीव में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचा है।

दोनों देश एक तीव्र संघर्ष में उलझ चुके हैं, जो दुनिया को वैश्विक युद्ध की ओर धकेल सकता है। इज़राइल का यह दावा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के कगार पर है, निराधार प्रतीत होता है, जैसा कि अमेरिका ने इराक के खिलाफ झूठा आरोप लगाया था कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, जो अंततः पूरी तरह गलत साबित हुआ।

विशेषज्ञों ने कहा, इसी रणनीति को दोहराते हुए, ट्रम्प प्रशासन के समर्थन से इज़राइल मीडिया में जोर-शोर से ऐसा प्रचार कर रहा है, ताकि ईरान पर हमलों को उचित ठहराया जा सके, तेहरान ने लगातार यह कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह किसी भी तरह के परमाणु हथियार कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

ईरान के शुक्रवार रात और शनिवार तड़के किए गए जवाबी हमलों से पहले, इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई ने टेलिविज़न पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ज़ायनिस्ट शासन को ''कड़ी सज़ा'' देने की बात कही थी।

इज़राइल के रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज़ ने तत्काल खामेनेई को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इज़राइली नागरिकों पर मिसाइलें दागनी जारी रखीं, तो ''तेहरान जल जाएगा''।

काट्ज़ ने एक बयान में कहा, ''ईरानी तानाशाह ईरानी नागरिकों को बंधक बना रहा है और उन्हें एक ऐसी स्थिति में ला रहा है, जिसमें वे, खासकर तेहरान के निवासी, इज़राइली नागरिकों को पहुँचे नुकसान की बड़ी कीमत चुकाएंगे। अगर खामेनेई ने इज़राइली इलाकों पर मिसाइलें दागनी जारी रखीं, तो तेहरान जलकर राख हो जाएगा''।

इस बीच, ईरानी हमले जारी रहने वाले हैं, और ईरान की फ़ार्स समाचार एजेंसी ने शनिवार को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि आने वाले दिनों में, इस क्षेत्र में स्थितअमेरिकी अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा।

वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हवाले से, फ़ार्स ने रिपोर्ट किया, ''यह टकराव बीती रात की सीमित कार्रवाई पर समाप्त नहीं होगा। ईरानी हमले जारी रहेंगे और आक्रांताओं के लिए यह काफ़ी दुखदायी और पश्चातापजनक होगा''।

- **दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है, रणनीतिक विशेषज्ञों ने कहा, यह स्थिति दुनिया को विश्व युद्ध के कगार पर ले जा सकती है।**
- **ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस को चेतावनी दी, अगर उन्होंने इज़रायल की मदद की तो ईरान उनके अड्डों व जहाजों को निशाना बनाएगा।**

अधिकारियों ने कहा कि यह युद्ध आने वाले दिनों में इस (इज़राइली) शासन द्वारा क़ब्ज़ा किए गए सभी क्षेत्रों और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी अड्डों तक फैल जाएगा।

ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने ईरान के इज़राइल पर हमलों को रोकने में मदद की, तो उनके अड्डों और जहाज़ों को भी निशाना बनाया जाएगा।

इज़राइल में हवाई हमले के सायरन पूरे देश में, विशेष रूप से तेल अवीव और यरुशलम में बजे, जिससे नागरिकों को बंकरों की ओर भागना पड़ा, क्योंकि ईरानी मिसाइलों की लगातार बारिश हुई और इज़राइली अवरोधक उन्हें रोकने के लिए सक्रिय हो गए।

इज़राइल की एम्बुलेंस सेवा के अनुसार, एक पुरुष और एक महिला की उस समय मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए, जब एक मिसाइल उनके घर के पास गिरी।

तेल अवीव के बाहर के शहर ऋशोन लेजिओन में ध्वस्त हुए अपार्टमेंट भवनों के मलबे में बचाव दल तलाशी अभियान चला रहे हैं।

फ़िलिस्तीनी रेड क्रेसेंट के अनुसार, ईरान समर्थित हूती मिलिशिया द्वारा यमन से दागी गई एक मिसाइल ने इज़राइल-आधिकृत वेस्ट बैंक में पाँच फ़िलिस्तीनियों, जिनमें तीन बच्चे शामिल थे, की जान ले ली।

तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया, तेहरान में शुक्रवार रात कई विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं।

ईरानी मीडिया ने बताया, ईरानी सशस्त्र बलों के दो उप-सेनापतियों की मौत इज़राइली हमलों में हुई। यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई, लेकिन उनकी मौत की जानकारी शनिवार को दी गई।

फ़ार्स समाचार एजेंसी के अनुसार, तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर दो मिसाइलें गिरीं, और ईरानी मीडिया ने वहाँ आग लगने की खबरें दीं। यह एयरपोर्ट ईरान के शीर्ष नेतृत्व के निकट स्थित है और वहां एक वायुसेना अड्डा भी है, जिसमें लड़ाकू और परिवहन विमान तैनात हैं।

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि इज़राइली हमलों में 78 लोग मारे गए, जिनमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं, और 320 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें अधिकांश नागरिक हैं।

दो अमेरिकन अधिकारियों ने बताया, अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को इज़राइल की ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद की। इज़राइल की सेना ने कहा कि ईरान ने शुक्रवार को 100 से कम मिसाइलें दागीं, जिनमें से अधिकांश को रोक लिया गया या वे लक्ष्य से चूक गईं।

दिनभर चले इज़राइली हमलों और उसके जवाब में हुई ईरानी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ा दी है, हालाँकि ईरान के सहयोगी ग़ाज़ा में हमास और लेबनान में हिज़्बुल्लाह पहले ही इज़राइल के हमलों में कमजोर हो चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी प्रमुख राफेल ग्रोसी ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद को बताया कि नतांज़ का पायलट परिशोधन केंद्र पूरी तरह नष्ट हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि फ़ोर्दो और इस्फ़हान में दो अन्य ठिकानों पर हुए इज़राइली हमलों की जानकारी अब भी एकत्र की जा रही है।

कांग्रेस में जातिगत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जातियों की पहचान को लेकर विवाद हो सकते हैं।

कुछ कांग्रेस नेताओं को यह भी चिंता है कि यह प्रक्रिया बाँटने वाली तथा जटिल हो सकती है तथा इसमें गलतियों की काफी संभावनाएँ हैं। कुल मिलाकर, यह समाज में नए तनाव पैदा कर सकती है।

भारत में आखिरी बार जातिगत आंकड़े 1931 में एकत्रित किए गए थे।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) करवाई थी, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए, क्योंकि इनमें विसंगतियाँ बताई गई थीं।

किन्तु आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस उस समय राजनीतिक जोखिम से बचना चाहती थी, क्योंकि ये आंकड़े आरक्षण नीति और सामाजिक समीकरणों को बदल सकते थे।

हालिया वर्षों में राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने जाति जनगणना का समर्थन खुलकर करना शुरू इसलिये किया है, क्योंकि वे सामाजिक न्याय और संसाधनों के पुनर्वितरण पर जोर देना चाहते हैं।

लेकिन पार्टी के भीतर विरोध की प्रमुख वजहें हैं जैसे, राजनीतिक समीकरण, जातिगत ध्रुवीकरण का डर, पारंपरिक वोट बैंक के दूर छिटक जाने की चिंता, इस मुद्दे पर ऐतिहासिक अनिर्णय।

विशेष रूप से भाजपा की ओबीसी वर्ग में बढ़ती पहुंच और क्षेत्रीय सहयोगी दलों के दबाव के मद्देनज़र, कांग्रेस अब इस मुद्दे पर अपना रुख अधिक स्पष्ट करती दिख रही है।

ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन अवरुद्ध होने के भय ...

- **भारत को ऑयल बॉण्ड, ऑयल पर लगी एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती आदि, सख्त कदम उठाने होंगे।**
- **पर, कितनी महँगाई बढ़ती है, आदि, आदि, इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान-इज़रायल युद्ध कितने दिन चलता है। पर, कटु सत्य है कि भारत का ''ग्रोथ मोमैन्टम'' तो पूर्णतया रूक जायेगा।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाद आर्थिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

शुक्रवार को भारतीय रुपया वैश्विक तेल मूल्य वृद्धि के प्रभाव में लगभग 0.6 प्रतिशत गिरा, जबकि शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यदि वर्तमान मूल्य स्तर बना रहा, तो घरेलू ईंधन की कीमतें 5 से 12 रूपए प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं। यह पूरे आर्थिक ढांचे में असर डालेगा, जिससे परिवहन, पैकेजिंग, कृषि और रसायन जैसे क्षेत्रों में लागत बढ़ेगी। ये क्षेत्र, जो तेल पर आधारित कच्चे माल पर निर्भर हैं, मार्जिन पर दबाव का सामना करेंगे और निर्माता यह बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं। महंगाई, जो हाल ही में नियंत्रण में आ रही थी, उसमें अचानक 0.5 से 1 प्रतिशत पॉइन्ट्स की बढ़ोतरी हो सकती है, यह इस पर निर्भर करेगा कि बढ़ते हुए तेल मूल्य कितने समय तक बने रहते हैं। नीति के स्तर पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती की कोई भी योजना टालनी पड़ सकती है।

वहीं वित्त मंत्रालय को ईंधन की कीमतों में तेज़ वृद्धि को रोकने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती पर विचार करना पड़ सकता है, जिससे उसकी आर्थिक गणना पर असर पड़ेगा। कमजोर होता रुपया डॉलर में तेल को और महंगा बना देगा, जिससे समस्या और जटिल हो जाएगी। हालाँकि भारत हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठा है। देश ने अपने ऊर्जा स्त्रोतों में विविधता लाने के लिए काम किया है, और अब वह रूस से रियायती दर पर तेल खरीद रहा है, अमेरिका से भी तेल ले रहा है और इराक तथा यूएई जैसे खाड़ी देशों पर अधिक निर्भर हो गया है। यदि कीमतें लंबे समय तक ऊँची बनी रहीं, तो रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, हालांकि यह अंतिम उपाय होगा।

घरेलू ऊर्जा और रक्षा विनिर्माण में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएँ भी भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सहनशक्ति का हिस्सा हैं, लेकिन ये तात्कालिक संकट का समाधान नहीं दे सकतीं।

अब आगे क्या होगा, यह संघर्ष की दिशा पर निर्भर करता है। यदि शत्रुता सीमित रहती है और इसका असर जहाजों के परिवहन या तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं पड़ता तो कच्चे तेल की कीमतें 75 से 80 डॉलर प्रति बैरल के बीच स्थिर हो सकती हैं, जो कष्टकारी तो है लेकिन इससे डील किया जा सकता है। मध्यम स्तर के बढ़ते संघर्ष के तहत, जिसमें बुनियादी ढांचे पर अप्रत्यक्ष हमले या क्षेत्रीय टैंकरों को खतरे शामिल हों तो तेल की कीमतें 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं। सबसे खराब स्थिति में, यदि होरमुज़ जलडमरूमध्य में पूरी तरह से नाकेबंदी या हमला होता है, कीमतें 120 डॉलर के पार जा सकती हैं, जिससे भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसी स्थिति में, महंगाई नाटकीय रूप से बढ़ेगी, रुपया गिरावट का सामना करेगा, और तथा केंद्र सरकार को प्रतिक्रियात्मक उपायों के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तेल बॉन्ड, उत्पाद शुल्क कटौती, और आयात विविधीकरण जैसी नीतिगत कुशनिंग कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन मूल समस्या बनी रहती है कि भारत की आर्थिक मशीनरी अब भी अस्थिर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की गिरफ्त में है, जहाँ भारी उतार-चढ़ाव है।

इज़राइल-ईरान संघर्ष ने भले ही भारत के हितों को सीधे निशाना नहीं बनाया हो, लेकिन इसके आर्थिक झटके पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। जब तक वैश्विक कूटनीति आगे बढ़कर तनाव को नियंत्रित नहीं करती, भारत का एक बार फिर बाहरी तेल संकट से जूझना पड़ सकता है, वो भी ऐसे समय में जब वह अपनी वृद्धि की गति को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा की लड़ाई अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गई बल्कि यह वास्तविक समय में घट रही है।

राहुल गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिक बेरोजगार युवाओं को नियुक्त पत्र सौंपेंगी। उन्होंने कहा कि बढ़ ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण युवाओं में बढ़ ती और नशे की लत मानसिक अवसाद को देखते हुये उन्हें इससे मुक्ति दिलाने के लिए यह कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट, एयरटेल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, महिन्द्रा, एमेज़ॉन, जेप्टो, टाटा, सैमसंग, हीरो, बजाज, वोल्टास, जस्ट डायल, वोडाफोन, ब्लिंकिट और रेडिसन जैसी प्रमुख कंपनियां उन लगभग 100 कंपनियों में शामिल हैं, जिन्होंने बेरोजगारों की सीधी भर्ती के लिए मैगा जॉब फेयर में भाग लेने पर सहमति जतायी है।

सीज़फायर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तबादला जैसलमेर किया था। अपील में कहा गया कि अब दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया है और तनाव के हालात समाप्त हो गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने आपदा प्रबंधन के तहत अपने कर्मचारियों के किए गए ट्रांसफर वापस ले लिए हैं।

राजस्थान का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुल 23 लाख 33 हजार 162 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और 13 लाख 15 हजार 853 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे।

इस वर्ष अनारक्षित श्रेणी के 689366, अनुसूचित जाति के 333646, अनुसूचित जनजाति के 150224, अन्य पिछड़ा वर्ग के 948507, ईडब्लूएस के 154326 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें छात्रों की संख्या 965996 और छात्राओं की संख्या 1310062 रही। इस वर्ष की परीक्षा में 939 विदेशी अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि 11 उभयलिंगी (थर्ड जेंडर) शामिल हुए।

अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित

केन्द्र सरकार ने इस 11 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की जो तीन माह में रिपोर्ट देगी

नयी दिल्ली, 14 जून। सरकार ने अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान की गुरुवार को हुई दुर्घटना की समग्रता से जांच के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो इस दुर्घटना को लेकर हर तरह के सवाल का जवाब तलाशेगी और तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने शनिवार को यहां उड़ान भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी और यह भी बताया कि विमान का डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स मिल गया और उसकी डिकोडिंग की जा रही है। नायडू ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि वे इस दुर्घटना के शिकार यात्रियों के परिजनों के दर्द को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने पिता को एक दुर्घटना में खोया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना होने के तीन घंटे बाद जब वे अहमदाबाद में घटनास्थल पर पहुंचे तो गुजरात सरकार की एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्य में लगे थे। विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (एएआईबी) ने अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में तकनीकी जांच शुरू कर दी है। इस जांच से उत्तर मिलेगा कि तकनीकी स्तर पर क्या कमी या चूक हुई थी।

नायडू ने कहा, पिछले दो दिन बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। अहमदाबाद हवाईअड्डे के पास हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं... मैं व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर गया, ताकि देख सकूँ कि क्या किया जाना चाहिए, क्या सहायता प्रदान की जानी चाहिए और यही रवैया गुजरात सरकार का भी था। भारत सरकार और मंत्रालय के अन्य लोगों का भी यही रवैया था। जब हम घटनास्थल पर पहुँचे, तो हमने देखा कि सभी संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया टीमें ज़मीन पर काम कर रही थीं, जो भी संभव हो, बचाव करने की कोशिश कर रही थीं, आग को कम करने और मलबे को हटाने की कोशिश कर रही थीं, ताकि शवों को जल्द से जल्द अस्पताल भेजा जा सके। विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो, जिसे विशेष रूप से विमानों के आसपास होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं की जाँच करने के लिए बनाया गया था, को तुरंत सक्रिय किया गया।

नाबालिग का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर बुलाया था और फिर वह उसे ट्रेन में बैठाकर अहमदाबाद ले गया। जहां उसे एक कमरे में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं, बाद में पुलिस और उसके परिजन आकर उसे ले आये। दूसरी ओर, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसके और पीड़ित पक्ष के बीच रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद था। ऐसे में द्वेषता के चलते उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

राजस्थान में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिसंचरण तंत्र सक्रिय है तथा एक पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावी है। इससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 14 जून से प्रदेश के कई जिलों-जैसे जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर व भरतपुर-में बादल, तेज़ आंधी (50-60 किमी/घंटा), बिजली की गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं।

इज़रायल-ईरान युद्ध से खाड़ी ...

- **प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा, जो जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर हैं, का कहना है कि इज़रायल ने पाकिस्तान की भांति, अमेरिका का ''स्टूज'' (पिछलग्गू) बनने का रास्ता अपनाया है तथा अमेरिका व यूरोपियन यूनियन के ''आदेशों'' की अनुपालना करने को तत्पर रहता है।**
- **प्रोफेसर पाशा की राय है, भारत के ईरान से गहरे सांस्कृतिक व इकोनॉमिक संबंध रहे हैं तथा अब इज़रायल से डिफैंस टैक्नॉलजी आधारित दोस्ती है। अतः भारत को अपनी इस अद्वितीय स्थिति को काम में लेते हुए दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति को शांत करने के लिए उपयोग करना चाहिए।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ - के इशारों पर चलने के मामले में इज़रायल का व्यवहार पाकिस्तान से अलग नहीं है। वह एक रणनीतिक कठपुतली बन गया है और उसकी एकतरफा कार्रवाहियाँ पूरे मध्य पूर्व को खतरे में डाल रही हैं। प्रो. पाशा ने यह भी कहा कि भारत सरकार को इस संकट के समय आगे आकर अपने इज़राइल और ईरान दोनों के साथ वर्षों पुराने संबंधों का उपयोग कर विवाद के कूटनीतिक समाधान की दिशा में पहल करनी चाहिए।

भारत, जिसने अब तक दोनों देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित रूप से बनाए रखा है, अब एक निर्णायक मोड पर खड़ा है। नई दिल्ली जहां एक ओर इज़राइल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी साझेदारी रखता है, वहीं ईरान के साथ उसके सांस्कृतिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंध भी गहरे हैं। वर्षों से भारत ने ईरान में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं, जैसे चाबहार बंदरगाह, में निवेश किया है, जो उसकी क्षेत्रीय संपर्क रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यमन, सीरिया और इराक में पहले से ही जारी तनावों के बीच, खाड़ी क्षेत्र में किसी भी नई अस्थिरता का असर पूरे दक्षिण एशिया और उससे आगे तक महसूस किया जा सकता है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, भारत सहित कई देश पर्दे के पीछे शांति वार्ता और तनाव कम करने के प्रयासों में जुटे हैं, ताकि एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध को टाला जा सके।

जैसे-जैसे यह संकट गहराता जा रहा है, आने वाले दिन भारत की कूटनीतिक क्षमता, आर्थिक सहनशक्ति और रणनीतिक दूरदर्शिता की कड़ी परीक्षा साबित होंगे, न केवल ऊर्जा सुरक्षा के लिए, बल्कि खाड़ी क्षेत्र से जुड़े लाखों जीवनों के लिए भी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908